



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229543
CG-DL-E-10092021-229543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943

No. 258]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

[मामला सं. एडी (एसएसआर)-24/2021]

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एमोक्सिसिलिन'/'एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट' के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत।

फा. संख्या 7/29/2021-डीजीटीआर.—यतः मै. अरविंदो फार्मा लि. (जिसे यहां आगे 'आवेदक'/घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एमोक्सिसिलिन'/'एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट' (जिन्हें आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन, पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी जारी है और संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति

होने की संभावना है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एमोक्सिसिलिन के आयातों से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा 27 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 14/5/2015-डीजीएडी, के माध्यम से शुरू की गई थी। दिनांक 3 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 14/5/2015-डीजीएडी के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 मई 2017 की अधिसूचना सं. 21/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

4. यह आवेदन मै. अरविंदो फार्मा लिमिटेड द्वारा घरेलू उद्योग के रूप में दायर किया गया है और मै. पेनाम लेबोरेट्रीज लिमिटेड तथा मै सेंट्रीएंट फार्मास्युटीकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित है। आवेदक ने न तो जाँच अवधि में संबद्ध देश से पीयूसी का आयात किया है और न ही उन्होंने संबद्ध देश में पीयूसी के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित होने का दावा किया है।

5. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक कंपनी का संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

6. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद "एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" है जिसे एमोक्सिसिलिन भी कहा जाता है। एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट एक अर्ध सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, जो एम्पीसिलीन का एक एनालॉग है, जिसमें अनेक ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव सूक्ष्म जीवों के खिलाफ जीवाणुनाशक गतिविधि का एक व्यापक स्पेक्ट्रम होता है। तथापि, निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:

- i. एमोक्सिसिलिन सोडियम स्टेरिल और फ्लुक्लोक्सासिलिन सोडियम स्टेरिल,
- ii. एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट कॉम्पैक्ट एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट कॉम्पैक्ट और
- iii. एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट और क्लवुलनेट पोटेशियम।

7. एमोक्सिसिलिन का उपयोग दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया की वृद्धि को कम करने के लिए किया जाता है। एमोक्सिसिलिन और अन्य जीवाणुरोधी दवाओं की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए, एमोक्सिसिलिन का उपयोग केवल उन संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाना चाहिए जो सिद्ध या अत्यधिक संदिग्ध रूप से बैक्टीरिया के कारण होते हैं।

8. एमोक्सिसिलिन को एक कार्बनिक रसायन होने के कारण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत 29411030 उपशीर्ष के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और भारत को संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु एक समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

संबद्ध देश

10. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि (पीओआई)

11. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2017-मार्च, 2018, अप्रैल, 2018-मार्च, 2019, अप्रैल, 2019-मार्च, 2020 की अवधियां और जांच अवधियां शामिल होंगी।

सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद (क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदक ने यह बताया है कि यदि प्रतिवादी चीन के उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है, तो सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के उपबंधों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।

13. आवेदक ने बताया है कि वह किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमतों अथवा भारत सहित ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों को कीमत संबंधी सूचना जुटाने में असमर्थ रहा है। अतः आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार “किसी अन्य तर्कसंगत आधार” के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का सुझाव दिया है। आवेदक ने चीन जन.गण. से 6-एपीए की निर्यात कीमत और भारत में मिथाइल एस्टर की आयात कीमत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का दावा किया है। इस प्रकार, ज्ञात कच्ची सामग्री की लागत तथा अंतिम उत्पाद को बनाने और बेचने के लिए अनुमानित परिवर्तन लागत तथा अन्य बिक्री और सामान्य प्रशासन, ऊपरी व्यय पर संबद्ध वस्तु के उत्पादन/बिक्री की लागत ज्ञात करने हेतु विचार किया गया है। संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए 5 प्रतिशत का लाभ जोड़ा गया है।

14. जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु आवेदक द्वारा सुझाई गई पद्धति पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

15. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत वाणिज्यिक असूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, संभलाई प्रभार, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार और गैर-वापसी योग्य वैट के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से अधिक है, जो दर्शाता है कि संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

17. इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि सकारात्मक पाटन मार्जिन, संबद्ध देश में उत्पादकों का निर्यातोन्मुख होना, संबद्ध देश में अप्रयुक्त क्षमताओं और संभावित व्यापार विपथन तथा भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता पर विचार करते हुए शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/ उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

प्रक्रिया

19. इस समीक्षा में दिनांक 3 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 14/5/2015-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित अंतिम जाँच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी यथाअपेक्षित पाटन और क्षति का संभावना विश्लेषण भी करेंगे।
20. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

21. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg12-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in, rajbir.sharma@nic.in और jd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
22. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

समय-सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाये कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाली सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पत्र भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
30. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना

या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोध साझा करना

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि सभी हितबद्ध पक्षकार अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

[Case No. AD(SSR)-24/2021]

Subject : Initiation of Sunset Review of anti-dumping duty imposed on imports of “Amoxycillin”/ ‘Amoxycillin Trihydrate’, originating in or exported from China PR.

No.7/29/2021-DGTR.—Whereas M/s Aurobindo Pharma Limited (hereinafter referred to as the applicant/domestic industry) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as

amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for Sunset Review of Anti - Dumping duty imposed on imports of Amoxycillin/ Amoxycillin Trihydrate (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “product under consideration” or PUC), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).

2. The Applicants has alleged that dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country has continued even after imposition of anti-dumping duty and there is a likelihood of continuation of dumping of the subject goods, and recurrence of injury to the domestic industry and has requested for extension of the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Background

3. The Authority had initiated the original investigation concerning imports of Amoxycillin originating in or exported from China PR vide Notification No. 14/5/2015-DGAD dated 27th April, 2016. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/5/2015-DGAD dated 3rd April, 2017 recommending imposition of definitive Anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR. Definitive anti-dumping duties were imposed by the Department of Revenue, Ministry of Finance, vide Notification No. 21/2017-Customs (ADD) dated 16th May, 2017.

Domestic industry & standing

4. The application has been filed by M/s Aurobindo Pharma Limited as the domestic industry and has been supported by M/s Penam Laboratories Limited and M/s Centrient Pharmaceuticals India Private Limited. The Applicant has neither imported the PUC from the subject country in the period of investigation nor is it claimed to be related to any exporter or producer of PUC in the subject country or any importer of the PUC in India.

5. As per the evidence available on record, the applicant company constitutes a major proportion of the total domestic production of the subject goods. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

Product under consideration

6. The product under consideration in the investigation is “Amoxycillin Trihydrate” also known as “Amoxicillin”. Amoxicillin Trihydrate is a semi synthetic antibiotic, an analog of ampicillin, with a broad spectrum of bactericidal activity against many Gram-positive and Gram-negative microorganisms. The following types of products are however, excluded from the scope of the product under consideration:

- i. *Amoxycillin Sodium Sterile and Flucloxacillin Sodium Sterile,*
- ii. *Amoxicillin Trihydrate Compacted Ampicillin Trihydrate Compacted and*
- iii. *Amoxicillin Trihydrate and Clavulanate Potassium.*

7. Amoxicillin is used to reduce the development of drug-resistant bacteria. To maintain the effectiveness of Amoxicillin and other antibacterial drugs, Amoxicillin should be used only to treat infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.

8. Amoxicillin being an organic chemical is categorized under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under subheading 29411030. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the investigation.

Like article

9. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from the subject country to India. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

Subject Country

10. The subject country in the present sunset review investigation is China PR.

Period of Investigation (POI)

11. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2020 to 31st March, 2021. The injury period of investigation will, however, cover the periods April, 2017-March, 2018, April, 2018-March, 2019, April, 2019-March, 2020 and the period of investigation.

Normal Value

12. The applicant has cited and relied upon Article 15 (a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to Rules.

13. The applicant has stated that it has not been able to gather information either with regard to costs or prices in a market economy third country, or price from such third country to other countries, including India. Therefore, the applicant has suggested normal value for China PR on the basis of "any other reasonable basis" as per Para 7 of Annexure I to the Rules. The applicant has claimed normal value by considering the export price of 6-APA from China PR and the import price of Methyl Ester into India. The cost of raw material so arrived along with the estimated conversion cost and other selling and general administration overheads to produce and sell the final product has been considered to arrive at the cost of production/sales of subject goods. Profit of 5% has been added to arrive at the normal value of the subject goods.

14. For the purpose of initiation, the Authority has considered the methodology suggested by the applicant for determination of normal value.

Export Price

15. The export price for subject goods from the subject country has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland freight, handling charges, marine insurance, bank charges, and non-refundable VAT.

Dumping Margin

16. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price, indicating that the subject goods are being dumped into Indian market by the exporters from the subject country.

Likelihood of continuation or recurrence of injury

17. There is prima facie evidence of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duty considering positive dumping margin, export orientation of the producers in the subject country, unutilized capacities in the subject country and potential trade diversion and price attractiveness of Indian market.

Initiation of Sunset Review Investigation

18. On the basis of the duly substantiated written application on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating likelihood of continuation/recurrence of dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country and injury to the domestic industry, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 23 of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Procedure

19. The review will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 14/5/2015 DGAD dated 3rd April 2017. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

20. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

21. In view of the special circumstances arising out of COVID- 19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg12-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in, rajbir.sharma@nic.in and jd14-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

22. The known producer/ exporters in the subject country, their Government through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the Domestic Industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

Time Limit

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit

Submission of information on confidential basis

28. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

30. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority

33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Sharing of responses/ submission amongst interested parties

36. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

Non-cooperation

37. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority